रोजगार के अवसरों का सृजन

3585. **चौधरी हरमोहन सिंह यादवः** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक एवं आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बेरोजगारी की संख्या कितनी कितनी थी,

(ख) चालू योजना अवधि के दौरान बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में क्या उपलब्धियां रही हैं,

(ग) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने के लिए उक्त नई नीति अपनाई है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) आठवीं योजना के आरम्भ में देश में अनुमानित बेरोजगारी लगभग 17 मिलियन थी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार रोजगार के अवसरों में 7.3 मिलियन प्रतिवर्ष की वृद्धि इंगित करते हुए 1987-88 से 1993-94 के दौरान 43.91 मिलियन की वृद्धि हुई। 1987-1988 से 1993-94 के दौरान परिलक्षित रोजगार वृद्धि दर में आठवीं योजना के प्रारम्भिक दो वर्षों को ही शामिल क्या गया। परवर्ती अवधि के रोजगार वृद्धि के अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) नौवीं योजना दृष्टिकोण में पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजित करने तथा गरीबी का उनमूलन करने की दृष्टि से कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की परिकल्पना की गई है। बेरोजगारी एवं अल्परोजगार की उच्च दरों की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों में श्रम सधन सैक्टरों सब सैक्टरों तथा प्रद्योगिकों पर संकेन्द्रण से विकास प्रक्रिया में अधिक उत्पादक रोजगार स्वतः ही सृजित होगा।

Enhancement of Gratuity payable to Employees

3586. SHRI KARNENDU BHATTACHARJEE: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Central :Government by an Ordinance have enhanced the gratuity payable to Employees and on the basis of this Ordinance Central Government employees are bemg paid enhanced gratuity with effect from 1st April, 1995 where as in case of other sections of employees enhanced gratuity is to be paid w.e.f. 24th September, 1997;

(b) if so, what are the reasons for this discrimination; and

(c) how. Government propose to remove this discrimination?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) to (c) The employees employed in the factories and certain other establishments are entitled to gratutiy as provided under the Payment of Gratuity Act, 1972. The Government has since amended the Payment of Gratuity Act and enhanced the ceiling on maximum amount of gratuity from Rs. 1.00 lakh to Rs. 3.50 lakhs w.e.f. the date of initial promulgation of the Ordinance i.e. from 24.9.1997. The maximum limit of Death-cUm-Retirement Gratuity (DCRG) under the CCS (Pension) Rules, 1972 was increased from Rs. 1.00 lakh to Rs. 2.50 lakhs w.e.f. 1.4.1995 as recommended by the Vth Pay Commission in its interim report and the same was further enhanced to Rs.3.50 lakhs w.e.f. 1.1.1996. As the provisions of the CCS (Pension) Rules are applicable to Government servants only, the question of extending it to non-Governmental employees does not arise.

Conviction under Section 406 and 409 of IPC

3587. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the number of employers who have been convicted under sectons 406 and 409
of IPC who have deducted employees' share of contribution but did not remit the same to the Employees Provident Fund; and smvolnm-:

' (B) the details of such employers?'

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) and (b) According to available information, during 1997-98 the employers belonging to the following establishments have been convicted under section 406^409 of the l.P.C.:—

1. MR. Rajaram Bandekar, Goa
2 MR A.V. Salmalkar, Goa
3. MR Rajaram Bandekar & Sons, Goa
4. MR. Bandekar Spec Valve Corpn, Goa
5. MR. Rajaram Bandekar & Co., Goa
6.MR. Rashmi Construction., Goa

Unemployed persons in the North East Region

3588. DR. B.B. DUTTA: .Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the number of unemployed persons in the North-East Region, State-wise;

(b) what has been the growth rate of employment in the North-East Region as compared to the country as a whole; and

(c) what are the plans to guarantee more employment opportunities for the youth of North-East Region?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) and (b) Rate of growth of employment and unemployment rates as per Ususal Principal Status in the North East Region, State-wise is enclosed as the statement *(See below).*

(c) The rate of growth of employment in a particular region depends on the pace and pattern of economic growth which is primarily a responsibility of State Govt. The Central Government is, however, implementing a number of self employment and wage employment progrlftimes throughout the country including the North East region.

Statement

Rates of Growth of Employment and Unemployment Rate in North Eastern States

States	Rate or Growth of Employment (UPS) (1987-88 to 1993-94)'	Unemployment Rat (%) (UPS) e
Arunachal Pradesh	4.84	1.21
Assam	1.00	7.58
Manipur	5.23	2.36
Meghalaya-	6.62	0.41
Mizoram	2.65	l.11
Nagaland	31.25	3.09
Tripura	4.72	3.52
ALL INDIA	2.37	2.56

Note(*): Growth rate of employment is at implied by employment estimates for the state based on the 43rd and 50th Rtend of National Sample Survey.

कर्माकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी

3589. **अनन्तराय देवशंकर दवेः** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विभिन्न राज्यों में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी का उद्यतन ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या कुछ निजी औद्योगिक घराने अपने कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं कर रहे हैं और वे विभिन्न श्रम संबंधी कानूनों तथा श्रम न्यायालयों के निर्णयों को लागु करने में पूर्णतया विफल रहे है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) उद्योगपतियों द्वारा विभिन्न श्रम कानूनों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार किया गया है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) विभिन्न राज्यों/संघ शसित क्षेत्रों में अकुशंस श्रेणी के कर्मकारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दवे के बारें में नीवनतम सूचना दर्शाने वाला एक विवरण संलग्र है (नीचे देखिए)

(ख) से (घ) संगठित क्षेत्र में मजदूरी का निर्धारण सामान्यता सामूहिक सौदेकारिता के आधार पर जबकि असंगठित क्षेत्र में मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत निर्धारित/संसोधित की जाती है।